ISSN 2455-5169

संपादकीय

असमानता की बढ़ती खाई और विकास के ढोल

महेश सिंह

आबादी के मामले में भारत दुनियां का दूसरा सबसे बड़ा देश है, साथ ही एक विशेषता और है कि इसे सबसे युवा देश होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि यहाँ 65 प्रतिशत आबादी की औसत आयु 35 साल से कम है। यह देखकर हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन शर्म इस बात की है कि इस युवा आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है।

आजादी के बाद हमारी सरकारें लगातार यह ढोल पीटती आयीं हैं कि देश, विकास की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते उपरी पायदान पर पहुंच गया है। नई सरकार तो इस मामले में मानों ढोल ही नहीं बल्कि ढोल के साथ भांगड़ा भी कर रही है। उसके द्वारा लगातार यह विज्ञापन दिया जा रहा है कि देश विकास कर रहा है, देश में अच्छे दिन आ गए हैं, जल्द ही हम दुनियां की महाशक्तियों की पंक्ति में होंगे आदि,आदि। कुछ लोगों के लिए यह सच हो सकता है और है भी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजगार घट रहा है। जैसे-जैसे देश में विकास हो रहा है, वैसे-वैसे असमानता अपने पांव पसार रही है। अमीरों और गरीबों के बीच एक गहरी खाई बनती जा रही है। समाचार एजेंसी ए. एन. आई की एक रिपोर्ट बताती है कि देश की पूरी आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीता है। 2017 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति 100वें स्थान पर आ गयी है, जबकि 2016 में हम 97वें स्थान पर थे।

आजादी के कुछ वर्षों तक हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, काफी हद तक हम इसमें सफल भी रहे लेकिन हालात तब ऐसे थे कि सुधार के आलावा विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन पिछले तीन दशकों से जारी निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने विकास की रफ़्तार को बहुत तेज कर दिया है। इस दौर में देश में पूंजी बहुत तेजी से बढ़ी है। "बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं कंपनी क्रेडिट सुईस ग्लोबल के अनुसार वर्ष 2000 से, भारत में मौजूद सम्पदा के कुल मूल्यों में हर साल 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है जबकि दुनियां के पैमाने पर यह औसतन 6 प्रतिशत रहा है."(*अप्रैल अंक 2018 मजदूर बिगुल*) इस तरह देश लगातार विकास की सीढ़ी चढ़ते चला जा रहा है। लेकिन यह विकास सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है, क्योंकि देश के सारे संसाधन मुट्ठीभर लोगों के हाथों में ही सिमटते जा रहे हैं और वे लोग पूरी तरह से वंचित हैं; जिनकी मेहनत से यह विकास होता है। अतः अमीरी और गरीबी की खाई लगातार और भी गहरी होती जा रही है।

ऑक्सफेम की रिपोर्ट 'बढ़ता अंतर : भारत असमानता रिपोर्ट 2018' के अनुसार; भारत में एक प्रतिशत लोगों के हाथों में देश की 58 प्रतिशत सम्पत्ति है और केवल 57 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश की 70 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है। यह रिपोर्ट देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो बिना लगाम वाली

सरकार को हमने बहुमत से चुना है। इस सरकार की दूरदृष्टि इस बात में देखी जा सकती है कि पढ़े-लिखे युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह देती है।

समस्या देश के विकास में नहीं, बल्कि देश के नाम पर किनका विकास हो रहा है, उसमे है। एक तरफ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरी में पूंजी का लगातार इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ देश की बड़ी आबादी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के लिए तरस रही है।

आज हम इक्कीसवीं सदी में हैं, लेकिन हमारी दशा अंधकार युग की है। तकनिकी और इंटरनेट सबकी पॉकेट में है, पर इसका सार्थक उपयोग कौन कर पा रहा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस हद तक गिरी हुयी है कि स्नातक होने के बाद भी हमें अपने मूल अधिकारों के बारे में पता तक नहीं, हम कानून का क-ख-ग भी नहीं जानते। यहाँ तक कि हम जिस विषय में स्नातक हैं, हमें उस विषय का दर्शन, इतिहास और वर्तमान कुछ भी नहीं पता। मैं उन इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों की बात कर रहा हूँ जो पूंजीपतियों और नेताओं द्वारा एक दुकान की तरह चलाया जाता है। आँखों देखी स्थिति यह है कि ऐसे कॉलेजों में छात्र एडमिशन लेने के बाद सीधे परीक्षा में ही नजर आते हैं। ऐसी शिक्षा से इन छात्रों की योग्यता क्या होगी ? तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग वे किस लिए करेंगे हम सभी जानते हैं।

यह तो हुयी उनकी बात, जो पूंजी के खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके आलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आई.आई.टी जैसे संस्थानों से निकले युवा भी रोजगार की खोज में भटक रहे हैं, या आधे से भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। समान काम के लिए समान वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक स्थायी सहायक प्राध्यापक को जहाँ लगभग 60 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता है, वहीं उसी काम के लिए अतिथि व्याख्याता के नाम पर 25 हजार रूपये मासिक पर काम करने के लिए पढ़े-लिखे युवा मजबूर हैं। यह एक प्रकार की बौद्धिक गुलामी है।

सरकार बहादुर आप विकास की बातें मन से कीजिये और हो सके तो होश में आइये, स्थिति दयनीय है संकट और गहराएगा। मैं यहाँ मजदूरों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका दर्द शब्दों बयाँ नहीं किया जा सकता। बाकी आप समझदार हैं।

इस अंक में,

प्रस्तुत अंक के बारें में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना ही काफी होगा कि यह अंक साहित्य, संस्कृति और सिनेमा की वैचारिकी में एक कदम और आगे बढ़ा है। इस अंक के सभी सहयोगी रचनाकार बड़ी सिद्दत से अपने-अपने विषय में गहन चिंतन और विश्लेषण करते हुए अपने विचार रखे हैं। आप भी पढ़िए यह अंक और अपने विचार हमसे साझा कीजिये। हमें इन्तजार रहेगा....!